विकेंद्रीकृत अभिशासन

मेंढा लेखा में एक सभा का दृश्य।

मेंढ़ा लेखा में कृषि भूमि और मछली (व अन्य प्राकृतिक संसाधन) भी अब सामूहिक स्वामित्व के अंतर्गत आते हैं।

'मुंबई और दिल्ली की सरकार तो हम सिर्फ चुनते हैं जबकि मेंढ़ा-लेखा में हम *खुद ही* सरकार हैं!'

महाराष्ट्र का मेंढ़ा-लेखा गांव अपने जंगल पर सामुदायिक अधिकारों की कानूनी लड़ाई जीतने वाले पहले दो गांवों में से एक था। इस गांव के आदिवासी समुदाय अपने प्राकृतिक संसाधनों के टिकाऊ इस्तेमाल के जरिए ठीक-ठाक आमदनी तो हासिल कर ही रहे हैं, इस संपदा का गांव के पुनर्निर्माण के लिए भी समतापूर्वक इस्तेमाल करते हैं। हाल ही में गांव के सभी निवासियों ने स्वेच्छापूर्वक अपनी सारी खेतिहर जमीन ग्राम सभा को सौंप दी है ताकि इन महत्वपूर्ण संसाधनों के निजी स्वामित्व को रोका जा सके।

इस फैसले ने ग्राम सभा को भी और मजबूती दी है। इससे ग्राम सभा को भोजन, पानी, आवास और शिक्षा के सामूहिक हितों पर गांव के भीतर और बाहर से पैदा हो रहे खतरों से निपटने की ताकत मिली है।

नागालैंड में सरकार द्वारा पूरे राज्य में सरकारी सेवाओं की डिलीवरी के रास्ते में आने वाली कठिनाइयों को समझने के लिए बहुत सारी कार्यशालाएं आयोजित की गईं थी। इससे कल्याण योजनाओं के निजीकरण की बजाय उनके सामुदायिकीकरण का सिलसिला शुरू हुआ था। इस प्रक्रिया के तहत समुदाय के लोग स्वास्थ्य (परंपरागत उपचार पद्धतियों सहित), शिक्षा और बिजली जैसे विभिन्न क्षेत्रों का स्वामित्व और प्रबंधन खुद संभाल सकते हैं।

सेंडेन्यू, नागालैंड में परंपरागत उपचारकों का एक समूह।

मेंढा लेखा, नागालैंड में सामुदायिकीकरण तथा पुणे में सहभागी बजटिंग जैसे उदाहरण एक वैकल्पिक राजनीति की आवश्यकता को दर्शाते हैं जो प्रत्यक्ष और प्रतिनिधित्व आधारित लोकतंत्र पर केंद्रित हो और जिसमें निर्णय प्रक्रिया आबादी की सबसे न्यूनतम इकाइयों से शुरू हो, जिसमें हर व्यक्ति के पास निर्णय प्रक्रिया में हिस्सा लेने का अधिकार, सामर्थ्य और अवसर हो और जो वंचित तबकों की जरूरतों और अधिकारों का सम्मान कर सके। इस तरह की राजनीति व्यक्तियों को उचित स्थान तो देगी मगर उन्हें इस स्थान को सामाजिक एवं पर्यावरणीय न्याय की सामूहिक प्राथमिकताओं की तरफ जिम्मेदारी निभाते हुए ग्रहण करना होगा।

खुज़मा, नागालैंड में एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र।